(b) if so, the details of issues discussed therein and the outcome thereof; and

(c) the follow up action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The following Agenda items were discussed in the meeting:—

(i) Sarkaria Commission Report, Chapter Vl-emergency Provisions; Recommendation for Amendment to Article 356 of the Constitution and other related Recommendations;

(ii) Guidelines for identifying and selection of issues and the procedure for conduct of business of the Council and its Committees;

(iii) Chapter-XI Economic and Social Planning;

(iv) Implementation Report on decisions of Inter-State Council on the Recommendations of the Sarkaria Commission. In the discussions there was no unanimity over articles 355 and 356 of the Constitution of India. However, the matter continues to be debated in a sub-committee set up by the Standing Committee of the Inter-State Council.

The Recommendations of the Inter-State Council will be communicated to the Union Ministries and the State Governments concerned for follow up action.

Illegal Bangladeshis in India

192. SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the special task force has reported presence of one crore and eighty lakh illegal Bangladeshi migrants settled in India, out of which 1.20 crores are in West Bengal alone;

(b) if so, the details thereof, Statewise; and

(c) what action is being taken/has been taken to repatriate those illegal settlers from the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b) It is difficult to make any exact estimate of the number of illegal immigrants from bangladesh because they enter surreptitiously and are able to mingle easily with the local population due to ethnic and lingustic similarities.

(c) A series of measures have been taken by the Government to curb the problem of infiltration of Bangladeshi nationals into India. These include raising of additional Battalions of Border Security Force, reduction of gaps between the border outposts, intensification of patrolling both on the land and the riverine border, accelerated programme of construction of border roads and fencing, increase in the number of outpost towers, provision of surveillance equipment etc. The matter has also been taken up with the Government of Bangladesh on various occasions. The progress of these measures is reviewed regularly at various levels. State Governments and Union Territory Administrations have also been directed to enforce the provisions of the Foreigners Act, 1946 (IMDT Act 1983 in caser of Assam) strictly.

Issuing of Citizens' Cards

193. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for issuing Citizens' cards for the entire population of the country;

(b) if so, the purpose, modalities and the probable date of issue; and

(c) whether these cards, if issued, would replace the Voters' Identity Cards?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) There is a proposal to issue multipurpose National Identity Cards to all the citizens of the country of and above the age of 14 years. These Cards are proposed to be used for the purpose of issuing passports, driving licences, ration cards, health care, admission in educational institutions, employment in public/private sectors, life and general insurance as also for maintenance of land records and urban property holdings etc. However, the proposal is at a conceptual stage.

मंत्रालयों के लिये प्रवेश हेतु विशेष पास

194. **प्रो0 रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या मंत्रालय द्वारा इसके विभिन्न कार्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष पास जारी करने के लिए कोई मानदंड/प्रक्रिया हैं, यदि हां, तो वह प्रक्रिया क्या हैं और क्या इसका अनुपालन हो रहा हैं,

(ख) क्या यह सच हैं कि इन पत्रों को जारी करने में भारी अनियमितता प्रकाश में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं,

(ग) यदि हां, तो इसमें उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण क्या हैं,

(घ) क्या सचिवालय सुरक्षा बल के सैंकड़ो कर्मचारियों ने उच्च स्तर के कुछ अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ गृह मंत्री से न्याय की गुहार की हैं, और

(ड़) यदि हां, तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अधीन आने वाले सरकारी भवनों (विशेष सुरक्षा कबर से अंतर्गत आने वाले कुछेक भवनों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए फोटो पास निम्नलिखित मानदण्डों और प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाते हैं **:-**

(i) राजपत्रित अधिकारियों को, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर, जिसे संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रयोजित किया गया हो ओपन फोटो पास जारी किए जाते हैं ।

(ii) अराजपत्रित कर्मचारियों को, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर जिसे विधिवत रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजति किया गया हो विशिष्ट भवनों के लिए प्रतिबंधित पास जारी किए जाते हैं । तथापि, कुछे मामलों में अराजपत्रित अधिकारियों को प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट सिफारिश पर उनकी कार्यात्मक अपेक्षाओं के आधार पर ओपन पास जारी किए जाते हैं ।

(iii) राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकारी उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को, निर्धारित प्रपत्र पर दिए गए आवेदन पत्र में दिए औचित्य के आधार पर जिसे संबंधित राज्य सरकारों या प्रशासिन मंत्रालयों/विभागों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रायोजित किया गया है, ओपन या प्रतिबंधित पास जारी किये जाते हैं ।

(iv) सर्विस एजेंसियों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, महानगर टेलीफोन निगम इत्यादि, द्वारा रखे गए कुछेक दिहाडी कर्मचारियों को भी, उनके कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर संबंधित एजेंसियों के प्रायोजन पर, पास जारी किए जाते हैं ।

(v) कुछेक, गैर-सरकारी व्यक्तियों को चुनिन्दा आधार पर ओपन या प्रतिबंधित पास जारी किए जाते हैं जो उनकी कार्यात्मक अपेक्षाओं और प्रत्येक मामले के गुण-दोश पर निभ्रर करता हैं ।

(vi) सरकारी भवनों में आगुन्तकों का प्रवेश, सचिवालय सुरक्षा संगठन के स्वागत कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले आगन्तुक पासों के जरिए विनियमित किया जाता हैं ।

उपरिल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को पास जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा हैं ।

(ख) और (ग) इन पासों को जारी करने में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं आई हैं ।